

अधूरी योजनाओं के सहारे पहाड़िया कैसे चढ़ें विकास के पहाड़



जसिन्ता केरकेट्टा

झारखंड के पाकुड़ जिले के कई पहाड़िया गांवों में कई सालों से योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। जबकि उनके समग्र विकास के लिए राज्य में कई योजनाएं चल रही हैं। योजनाओं की राशि इतनी है कि पहाड़ियाओं का जीवन बदल सकता है लेकिन अधूरी योजनाओं के सहारे पहाड़िया कैसे चढ़ें विकास के पहाड़ ? कई गांवों में कोई भी योजना नहीं पहुंची है। उस पर प्रधानमंत्री की गुजरात मॉडल पर आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के समग्र विकास के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। हकीकत की जमीन पर सारी योजनाएं क्यों अधूरी हैं ? जिले में इसे जानबूझ

कर नजरअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ कागज पर योजनाएं पूर्ण हैं। आदिवासियों व आदिम जनजातियों के समग्र विकास के लिए पूर्व से बनी योजनाओं का हाल यह है तो यह नई योजना से किसका समग्र विकास होगा। यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला मुख्यालय से मात्र सात किलोमीटर दूर है एक पहाड़िया गांव पतरापाड़ा। गांव में माल पहाड़िया आदिम जनजातियों का निवास है। गांव की आबादी 370 है। जिसमें आधा आबादी पिछड़ी जाति की है। गांव में पहाड़िया व पिछड़ी जाति की आबादी लगभग बराबर-बराबर है। पहाड़िया टोले में प्रवेश करते ही दिखता है पक्के घरों की पक्की खड़ी

दिवारें व पीलर मगर ये अधूरे घर हैं और इसपर झूलते हैं लौकी और नेनुआ की लतर। पहाड़ियाओं के लिए खास तौर पर बिरसा आवास योजना है। जिसके तहत गांव में आठ बिरसा आवास बने हैं। पूरे गांव में बिरसा आवास की पक्की पीलर लगी हुई है लेकिन वे सभी अधूरी हैं। इस वजह से लोग बगल में ही मिट्टी का घर बनाकर रह रहे हैं। इन अधूरी दीवारों ने उनकी जमीन पर कब्जा तो जमा लिया है लेकिन ये उन्हें आश्रय दे पाने में असमर्थ हैं। गांव में नौ इंदिरा आवास में दो बनकर पूरा हुआ है और सात अधूरा है। शौचालय बनने का काम शुरू हुआ है गांव में यह आधा बनकर रूका हुआ है। लोगों

को डर है कि बिरसा आवास की तरह कहीं शौचालय भी हमेशा के लिए अधूरा न रह जाए। गांव में अधिकांश लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। मुख्यमंत्री अंतोदय योजना के तहत उन्हें चावल पाने का अधिकार है लेकिन गांव के अधिकांश पहाड़िया परिवारों को चावल प्राप्त नहीं होता। गांव में विधवाओं की संख्या अधिक है। ऐसा लगता है यह विधवाओं का गांव है लेकिन किसी विधवा को विधवा पेंशन नहीं मिलता। इसी तरह वृद्धा पेंशन भी किसी को नहीं मिलता। गांव की तारामुनी पूजहरनी कहती हैं कि बीपीएल कार्ड आज तक नहीं बना है। कार्ड न होने के कारण बीपीएल को मिलने वाली सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिलती। रणोती पूजहरनी का कहना है कि आंगनबाड़ी में समय पर पोषाहार न मिलने के कारण बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता है।

गांव में किसी के पास नहीं है जाति प्रमाण पत्र : आदिम जनजाति पहाड़ियाओं के लिए बनी योजनाओं से गांव को जोड़ा तो गया है, लेकिन इस गांव के पहाड़िया आदिम जनजाति के लोगों का भविष्य खतरे में है। लोगों के खतियान में जाति की जगह माल पहाड़िया न होकर इनका गोत्र पूजहर अंकित है। जिसके कारण

कई सालों से इस गांव के पहाड़िया अपनी जाति के पहचान से वंचित हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे। इसमें सुधार के बदले उनके गांवों तक आदिम जनजातियों के लिए बनी योजनाएं तो पहुंच रही लेकिन उनके पास स्वयं की जाति प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। ग्रामीण लाल पूजहर का कहना है कि उनकी संस्कृति, विवाह के रीति-रिवाज, भाषा के अनुसार वे माल पहाड़िया हैं लेकिन खतियान में प्रारंभ से ही गलती न सुधारे जाने के कारण उनका गोत्र ही उनकी जाति बन गया है। जबकि पूजहर नाम की कोई दूसरी जाति नहीं है। माल पहाड़ियाओं के गोत्र में पूजहर भी एक है। इसके कारण गांव के किसी भी पहाड़िया के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। बच्चों को भी भविष्य में इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए यह बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। इसके बावजूद जानकारों के कहने पर गांव के लोगों तक आदिम जनजाति को मिलने वाली योजनाएं पहुंच तो रही लेकिन योजनाएं कभी पूरी नहीं हुई हैं।

जारी

सीएसडीएस द्वारा प्रदत्त
इनक्लूसिव मीडिया
यूनडीपी फेलोशिप के तहत